

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लंकार

बनाम

विपक्षी : श्री भगवानलाल व अन्य

किरम मुकदमा - 128 मूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या 05/2022

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक 28.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। प्रकरण में

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की विपक्षी द्वारा दिनांक 28.08.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में प्रार्थीगण

जिस भूमि की पत्थरगद्दी करवाने चाहते हैं। वह हमारे परिवार की मौजूदगी जायदाद है

जिसका लेकर आप माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद अभी माननीय राजस्व मण्डल

अजमेर की पत्रावली में गया हुआ है साथ ही स्थगन प्रकरण संख्या 35/25 प्रार्थना पत्र

अनवान नानी चाई बनाम मोहन आप माननीय न्यायालय में विचाराधीन होकर नियत है

जिसकी जानकारी इस प्रकरण के प्रार्थीगण को अच्छी तरह से है एवं उपरोक्त तथ्यों को

छिपाकर प्रार्थीगण ने पत्थरगद्दी का प्रकरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण के प्रार्थीगण

पत्थरगद्दी की आड में विपक्षीगण से जबरन मौजूदगी जायदाद से कब्जा छिनना चाहते हैं

एवं स्थगन पत्रावली के तथ्यों को छिपाकर बदनियती से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः

प्रार्थना पत्र 128 मूराजस्व अधिनियम का खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी की तरफ से उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब पेश कर

बताया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं आधिपत्य की जमीन की पत्थरगद्दी कराने चाहते

हैं जिनका उनको विधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि पत्थरगद्दी मात्र सीमांकन के लिये की

जाती है उससे कोई हक अधिकार तय नहीं होते हैं। प्रार्थीगण ने न्यायालय के सम्क्ष

किरी भी प्रकार के तथ्य छिपाये नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने

का निवेदन किया।

हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 128 मूराजस्व अधिनियम के

तहत पेश कर मौजा लूणदा पटवार हल्का लूणदा तहसील कानांड की खाता न. 138 की

आराजी न. 504, 505, 506, 511, 515 किता 5 रकबा 0.8300 है, भूमि की पत्थरगद्दी किये

जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि

से संबंधित मूल वाद राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। अतः मूल वाद विचाराधीन

होने से प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के पश्चात पुनः पेश किये

जाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता

है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

